

स्वास्थ्य व्यय पर NHA रपिर्ट

प्रलिस के लयल:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, सकल घरेलू उत्पाद

मेन्स के लयल:

स्वास्थ्य व्यय पर NHA रपिर्ट के प्रमुख बढल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) ने बताया कसरकार ने स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धकी है, जससे आउट-ऑफ पॉकेट एक्सपेंडचर (OOPE) वर्ष 2017-18 में घटकर 48.8% हो गया, जो वर्ष 2013-14 में 64.2% था ।

- यह रपिर्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र द्वारा तैयार की गई थी, जससे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) तकनीकी सचवालय के रूप में नामलि कयल गया था ।
- वश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वास्थ्य खातों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रणाली 2011 के आधार पर एक लेखा ढाँचे का उपयोग कर NHA अनुमान तैयार कयल जाते हैं ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र:

- यह 2006-07 में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मशिन (NRHM) के तहत तकनीकी सहायता के लयल एक शीर्ष नकलय के रूप में कार्य करने हेतु स्थापलि कयल गया था ।
- इसका अधलदेश स्वास्थ्य और परवलर कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के लयल राज्यों को तकनीकी सहायता के प्रावधान करने और क्षमता नरमाण हेतु नीतलएवं रणनीतल बनाने में सहायता करना है ।

प्रमुख बढल

- कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी हसलसेदारी में वृद्धल:
 - 2017-18 के लयल देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय के हसलसे में वृद्धलहुई थी ।
 - यह वर्ष 2013-14 के 1.15% से बढकर वर्ष 2017-18 में 1.35% हो गया है ।
- प्रतलव्यक्तल बढल हुआ सरकारी खर्च:
 - वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के बीच प्रतलव्यक्तलके हसलब से सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1,042 रुपए से बढकर 1,753 रुपए हो गया है ।
- प्राथमकल स्वास्थ्य देखभाल का हसलसा:
 - वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय में प्राथमकल स्वास्थ्य सेवा का हसलसा 2013-14 के 51.1% से बढकर 2017-18 में 54.7% हो गया है ।
 - प्राथमकल और माध्यमकल देखभाल वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय के 80% से अधकल के लयल ज़मलमेदार है ।
- स्वास्थ्य पर सामाजकल सुरक्षा व्यय:
 - स्वास्थ्य पर सामाजकल सुरक्षा व्यय का हसलसा, जसलमें सामाजकल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सरकार द्वारा वतलतपोषतल स्वास्थ्य बीमा योजनलएँ और सरकारी कर्मचारयों को की गई चकलतलसा प्रतलपूरतल शामिल है, में वृद्धलहुई है ।
- जब खर्च में कमी:
 - स्वास्थ्य देखभाल पर सरकारी खर्च में वृद्धलके कारण कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी खर्च का हसलसा बढकर 40.8 फीसदी हो गया और 2017-18 के लयल जब खर्च में 48.8% की गरलवट आई ।
 - OOPE में गरलवट सरकारी स्वास्थ्य सुवधलओं के बढते उपयोग और इन सुवधलओं एवं सेवाओं की लागत में कमी के कारण है ।

स्वास्थ्य क्षेत्र के मुद्दे:

- **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अभाव:** देश में मौजूदा सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल का दायरा सीमित है।
 - जहाँ तक एक अच्छी तरह से काम करने वाले सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात है तो वहाँ केवल गर्भावस्था देखभाल, सीमिति चाइलडकेयर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित कुछ सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- **आपूर्ति-पक्ष की कमियाँ:** बदतर स्वास्थ्य प्रबंधन कौशल और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिये उचित प्रशिक्षण एवं सहायक पर्यवेक्षण की कमी स्वास्थ्य सेवाओं की वांछित गुणवत्ता के वितरण को अवरुद्ध करती है।
 - वर्ष 2019 में जॉन्स हॉपकिंस बलूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रत्येक 100 में से लगभग एक बच्चे की मृत्यु दस्त या नमोनिया के कारण पाँच वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती है।
 - स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुँच का प्रत्यक्ष संबंध डायरिया, पोलियो और मलेरिया जैसी बीमारियों से है।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण:** भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण पर व्यय लगातार कम हो रहा है (जीडीपी का लगभग 1.3%)। भारत का कुल 'आउट-ऑफ-पॉकेट' व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.3% है।
 - यह आवंटन 'आर्थिक सहयोग और विकास संगठन' (OECD) देशों के औसत (7.6%) और ब्रिक्स (BRICS) देशों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर किये जाने वाले औसत खर्च (3.6%) की तुलना में काफी कम है।
- **अतव्यापी क्षेत्राधिकार:** सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु उत्तरदायी कोई एक वशिष्ट प्राधिकरण नहीं है, जो कानूनी रूप से दिशा-निर्देश जारी करने एवं स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन को लागू करने हेतु अधिकृत है।
- **उप-इष्टतम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली:** इसके कारण उन गैर-संचारी रोगों से नपटना चुनौतीपूर्ण है जहाँ रोकथाम और रोग की आरंभिक पहचान सबसे महत्वपूर्ण होती है।
 - यह कोविड-19 महामारी जैसे नए और उभरते खतरों के लिये पूर्व-तैयारी और प्रभावी प्रबंधन की क्षमता को सीमित करती है।
- **आवश्यकता से कम डॉक्टर:**
 - भारत में वर्तमान में WHO के 1:1000 के मानदंड के मुकाबले 1,445 की आबादी पर एक ही डॉक्टर मौजूद है।

संबंधित सरकारी पहलें:

- [जननी शशि सुरक्षा कार्यक्रम \(JSSK\)](#)।
- [राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम \(RBSK\)](#)।
- [निःशुल्क दवाओं और निःशुल्क नदिन सेवा पहलों का कार्यान्वयन](#)।
- [प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम](#)।
- [आयुष्मान भारत](#)।
- [प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना \(AB-PMJAY\)](#)

आगे की राह

- लागत को कम करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु मेडिकल कॉलेजों में नविश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- अन्य नैदानिक प्रक्रियाओं और अस्पतालों में सार्वजनिक नजिी भागीदारी (PPP) पर जोर देना तथा लक्ष्य की त्वरित प्राप्ति के लिये टीकाकरण अभियान में नजिी क्षेत्र की वशिषज्जता का लाभ उठाना।
- नई दवाओं के विकास में अधिक नविश का समर्थन करने और जीवन रक्षक व आवश्यक दवाओं पर 'वस्तु एवं सेवा कर' को कम करने के लिये अतिरिक्त कर कटौती द्वारा अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करना।
- लोगों को प्रस्तावित स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु मौजूदा स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को तैयार करने के लिये उनके प्रशिक्षण, पुनः कौशल और ज्ञान अन्नयन पर ध्यान देना आवश्यक है।

स्रोत: द हद्दि